श्री अटल बिहारी वाजपेयी : स्टेटमेंट हिन्दी में है, लेकिन रिपोर्ट हिन्दी में नहीं है। यह बहाना नहीं चलेगा कि यह एक मोटी किताब है, इस लिए इस का हिन्दी रूपान्तर तैयार करना कठिन है।

श्री धर्मवीर सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रभाषा के प्रति मेरे मंत्रालय में अनादर की भावना नहीं है। अगले वर्ष से यह रिपोर्ट हिन्दी में भी रखी जायेगी।

13.04 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Navy (Amendment) Bill, 1973, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd November, 1973."

NAVY (AMENDMENT) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table of the House the Navy (Amendment) Bill, 1973, as passed by Rajya Sabha.

13.05 hrs

BURN COMPANY AND INDIAN STANDARD WAGON COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL*

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI T. A. PAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the taking over, in the public interest, of the management of the undertakings of certain companies, pending nationalisation of such undertakings, with a view to ensuring rational and co-ordinated development and production of rolling stock, other products of iron and steel industry and other goods needed by such industry, and for matters connected therewith or incidental thereto.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, इस में तीन मुद्दे उठते हैं।

पहला तो यह कि आज सवेरे इस विधेयक के साथ जो वक्तव्य परिचालित किया गया है, उस में मंत्री महोदय ने कारण बताया है कि वह दो दिन का नोटिस क्यों नहीं दे पाये। अगर आप इस को एक औपचारिक बात समझते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आप इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्ज को देखेंगे, तो आप को पता चलेगा कि यह मामला बहुत पुराना है। अर्से से मजदूर संगठन इस के बारे में शिकायत कर रहे थे। इन कम्पनियों में घोटाला, अव्यवस्था और बद-इन्तजामी थी। तो फिर मंत्री महोदय को ऐसा कौन सा विलम्ब का कारण हुआ कि वह दो दिन का नोटिस नहीं दे सकते थे? अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर आप को निर्णय करना है। आप इस बारे में एक आदेश जारी कीजिए।

दूसरे, मेमोरेंडम रिगार्डिन्ग डेलीगेटिड लेजिसलेशन में कहा गया है कि यह एक साधारण नियम बनाने का प्रावधान है, डेलीगेटिड लेजिसलेशन है। लेकिन यदि आप इस विधेयक की धारा 4 की ओर ध्यान देंगे, तो आप को पता चलेगा कि इन कम्पनियों के सरकार के हाथ में चले जाने के बाद उन के ढांचे के बारे में क्या योजना होगी, उस की क्या रूपरेखा होगी, इस का

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 28-11-73.

[श्री मधु लिमये]

जरा भी उल्लेख नहीं है । सारे अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले रखे हैं । क्या मंत्री महोदय को इस विधेयक में यह सूचित नहीं करना चाहिए था कि इन कम्पनियों का ढांचा और रूपरेखा यह होगी ? अगर सरकार तफ़सील के बारे में नियम बनाने के अधिकार ले, तो यह सदन कोई एतराज नहीं करेगा ।

MR. SPEAKER: These principles of the Bill you could discuss at the first reading of the Bill. Your first objection was perfectly valid at the introduction stage of the Bill. But if you want to discuss the principles of the Bill, that you can do at the first reading of the Bill.

श्री मधु लिमये : तीसरा मुद्दा यह है । आप धारा 5 को देखिए । सरकार बर्न एण्ड कम्पनी को पचास हजार रुपये देने जा रही है । जब उस ने संविधान में इतने परिवर्तन किए हैं, तो फिर जिन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, जिस के कारण सरकार इन कम्पनियों को अपने हाथ में ले रही है, क्या मंत्री महोदय उन को पचास हजार या पच्चीस हजार रुपये तोहफ़े के रूप में दे रहे हैं ? इस की कोई वजह होना चाहिए ।

MR. SPEAKER: That is also for the first reading stage. The hon. Minister.

SHRI T. A. PAI: Mr. Speaker, Sir, we had complaints regarding the problems that were existing in this unit. We were observing its functioning for a long time. We also carried out investigations and we were satisfied that such an action was necessary under the Industrial Development and Regulation Act. We also found that certain sections of the Company were working satisfactorily and therefore, it would not be possible for us to take over only losing sections of the Company, leaving out the cream of business to the industry itself. Ultimately, we thought that the only option given to us under the circumstances was to take over the management of the Company initially and nationalise it thereafter.

We wanted to do it through an Ordinance because in a concern like this, where complaints were being made that the properties were being transferred, that the assets were being liquidated, we had to take quicker action. But there has always been a complaint that the Government is running on Ordinances. I was advised that I must introduce a Bill for that this time. So, I have come forward with the Bill. Nevertheless, I have got to request the House to get the Bill through quickly because we are anxious to take possession of the assets of the Company and leave the minimum time for any kind of diversion. That was the reason why I wanted you, Sir, and the House to give me this permission to have the Bill through as quickly as possible. We have decided upon the management; the set-up has also been decided upon; we have decided who should take over on behalf of the Government. All those details have been worked out. In order to see that in the meanwhile, there is no diversion, Government has taken some steps which, I do not think, it is in public interest for me to disclose. Nevertheless, in the Bill itself we have provided that the transfers which are not *bonafide* prior to six months of the appointed day are going to be null and void. I hope, the hon. Member would agree with this and permit me to introduce the Bill.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the taking over, in the public interest of the management of the undertakings of certain companies, pending nationalisation of such undertakings,

with a view to ensuring rational and coordinated development and production of rolling stock, other products of iron and steel industry and other goods needed by such industry, and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI T. A. PAI: Sir, I introduce the Bill.

13.12 hrs.

ALCOCK ASHDOWN COMPANY LIMITED (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS) BILL*

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI T. A. PAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the acquisition of the undertakings of the Alcock Ashdown Company Limited for the purpose of ensuring rational and coordinated development and production of goods essential to the needs of the country in general, and defence department in particular, and for matters connected therewith or incidental thereto.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, इस के बारे में तथ्य है कि यह कम्पनी 1965 तक तो मुनाफे में चल रही थी। उस के बाद घाटा होने लगा और तीसरी लोक सभा में इस कम्पनी का मामला बार बार उठाया गया। मेरे मित्र माननीय सदस्य श्री मधु दण्डवते जी ने पांचवी लोक सभा में भी इस की कई दफा चर्चा उठाई। कम्पनी ला के तहत इन के इतने व्यापक अधिकार हैं, उन अधिकारों का इन्होंने इस अवधि में इस्तेमाल क्यों नहीं किया ? ... (**व्यवधान**) ... अध्यक्ष महोदय, आप को इन चीजों के बारे में कुछ आदेश देना चाहिए, डायरेक्शन देनी चाहिए ....

अध्यक्ष महोदय क्या आदेश देना चाहिए, आप बताएं।

श्री मधु लिमये : जब बार बार सदस्य किसी एक चीज के बारे में यहां सवाल उठाते हैं कि कम्पनी ठीक ढंग से नहीं चल रही है तो क्या समय पर कम्पनी ला बोर्ड को और कम्पनी ला अफेयर्स के मंत्री को जांच करके आवश्यक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए ? सारा कैपिटल खाने के बाद आप लोग कम्पनी लेंगे, सारे जंक को लेंगे ? एक बात और मुझे इस के बारे में कहनी है कि एक करोड़ रुपया ये दे रहे हैं। क्या इस विधेयक में यह जरूरी नहीं है ... (**व्यवधान**) ... अध्यक्ष महोदय, मैं संसद् के अधिकारों की बात कर रहा हूं। क्या इन्हें हम लोगों को ब्रेक अप नहीं देना चाहिए कम्पनी के बारे में आप इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं....

MR. SPEAKER: Why do you discuss at this stage matters which can be discussed only in the First Reading? You are going into the details of the Bill.

श्री मधु लिमये : नहीं, मैं वह नहीं कह रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं प्रेजेन्टेशन के बारे में कह रहा हूं। बिल को रखा कैसे जाय इस के बारे में कह रहा हूं। जब एक करोड़ रुपया मुआवजा देने की बात है तो क्या इस सदन को यह पता नहीं होना चाहिए कि इस कम्पनी का कैपिटल कितना है, इस में कौन कौन लोग हैं (**व्यवधान**) ....

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): We want to know the financial involvement of the Government if and when it takes over, and the second point is about absorption of the employees.

Introduced with recommendation of the President.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 28-11-73.